राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF RURAL
DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
Ministry of Rural Development, Government of India
www.nirdpr.org.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रगति
समाचार पत्र



उत्तरजीविता से सशक्तिकरण की ओरग्रामीण ट्रांसजेंडर समुदायों के सामुदायिक संस्थानों : एवं आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में।

अंक 373 जून 2026

इस अंक में .....

आवरण कहानी: **जीविका निर्वाह से आत्मनिर्णय तक: ग्रामीण किन्नर समुदायों के सामुदायिक संस्थानों और आजीविका के मार्गों को सुदृढ़ करने की दिशा में** -4

1. डीएवाई -एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यम ऋण आवेदन (आईईएलए) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - 9
2. लखपति दीदी पहल के अंतर्गत बाजरा एवं सोया-आधारित उत्पाद बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण - 10
3. व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों एवं पीएसीसीएस की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम -11
4. सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण पद्धति एवं प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करने पर टीओटी -12
5. ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु अनुकूल एवं कार्बन तटस्थ योजना पर टीओटी -13
6. डेएनआरएलएम- के अंतर्गत जोखिमआधारित आंतरिक - लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण -14
7. मालदीव गणराज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम - 15
8. बीआईपीएआरडी, गया में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पूर्ण संतृप्ति लाने एवं समृद्ध ब्लॉक बनाने के लिए बीडीओ नेतृत्व पर ऑफकैंपस - प्रशिक्षण -16
9. एसआरएलएम के विकास पेशेवरों के लिए नेतृत्व कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम - 18
10. आईईएस बैच 2026 के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए ग्रामीण विकास के मुद्दों, चुनौतियों, हस्तक्षेपों एवं प्रभावों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम - 19
11. नागालैंड एसआरएलएम के सीआरपी-ईपी के लिए सीएमपीआरपीईडी, एनआईआरडीपीआर के दिल्ली शाखा द्वारा विपणन कौशल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम - 21
12. संकाय विकास कार्यक्रम (बैच VI) - 23
13. यूबीए प्रगति रिपोर्ट: एमजेसीईटी ने यूबीए संपर्क पहल के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा को सुदृढ़ किया - 24

15. एनआईआरडीपीआर द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का आयोजन - 25

16. 30–दिवसीय सामुदायिक लेखा परीक्षक प्रमाणन कार्यक्रम -26

17. आजीविका, स्वयं के स्रोत से राजस्वएवं समावेशी विकास के (ओएसआर) नेतृत्व वाले ग्रामीण हाट प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला-लिए पंचायत -27

18. राष्ट्रीय स्रोत व्यक्तियों के लिए एकल सुविधा केंद्र की (ओएसएफ) कार्यान्वयन रणनीति पर कार्यशाला -28

19. एनआईआरडीपीआर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का आयोजन -29

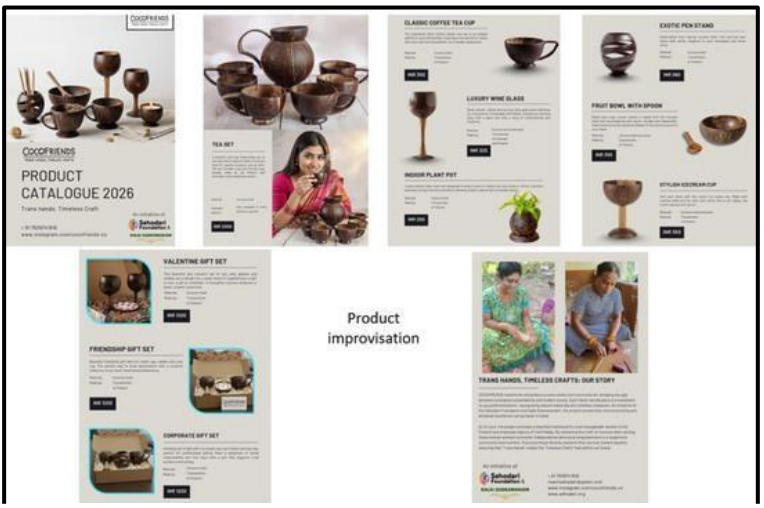
20. ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (जीपीडीपी) तैयार करने पर कार्यशाला (एसओपी) -30

21. स्वयं के स्रोत से राजस्व (ओएसआर) में वृद्धि एवं नवाचार की रणनीतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला - 31

22. **विद्यार्थी कॉर्नर :** पलायन पर कौशल की जीत एक व्यक्ति जिसने गाँव की सोच बदल दी -32

जीविका निर्वाह से आत्मनिर्णय तकग्रामीण किन्नर : समुदायों के सामुदायिक संस्थानों और आजीविका के मार्गों को सुदृढ़ करने की दिशा में

डॉसंध्या गोपकुमारन .
निदेशक, डीडीयूजीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ-, एनआईआरडीपीआर
sandhya@nird.gov.in



प्रशिक्षित किन्नर उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए पर्यावरणअनुकूल-नारियल के खोल से बने उत्पादों को दर्शाती कोकोफ्रेंड्स कैटलॉग



सिलाई एवं परिधान उत्पादन प्रशिक्षण

प्रगतिशील कानूनी मान्यता और नीतिगत प्रतिबद्धताओं के बावजूद, किन्नर और लैंगिक विविधता वाले युवा शिक्षा प्रणालियों, श्रम बाजारों तथा संस्थागत सहायता तंत्रों से लगातार वंचित हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आजीविका में दीर्घकालिक असुरक्षा बनी रहती है।

विशेष रूप से वर्ष 2025 में, डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ ने निम्नलिखित की पहचान करने के लिए दो पहलें कीं: (i) वे प्रणालीगत और संरचनात्मक कमियाँ, जो ग्रामीण किन्नर व्यक्तियों को सम्मानजनक एवं सतत आजीविका के अवसरों तक पहुँचने और उन्हें बनाए रखने में बाधा डालती हैं। (ii) विद्यमान आजीविका मॉडल, जिनमें टिकाऊ बने रहने की क्षमता है। (iii) वे प्रमुख सहायक कारक, जो नीतियों और व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच सेतु का कार्य करते हैं।

पहली परियोजना एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (सीआईआरडीएपी) के सहयोग से संचालित की गई तथा दूसरी परियोजना कनाडा उच्चायोग के कनाडा फंड फॉर लोकल इनिशिएटिव्स (सीएफएलआई) के सहयोग से संचालित की गई।

परियोजना 1: मुख्यधारा की आजीविका में किन्नर एवं जेंडर विविधता वाले युवाओं को शामिल करने के लिए कार्य प्रयोगशाला

मुख्यधारा की आजीविका में किन्नर एवं लैंगिक विविधता वाले युवाओं को शामिल करने के लिए कार्य प्रयोगशाला का कार्यान्वयन सीआईआरडीएपी के महिला, युवा एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूवाईआरपी) के अंतर्गत किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समूहों में से एक–किन्नर एवं लैंगिक विविधता वाले व्यक्तियों–के लिए समावेशी एवं सतत आजीविका के मार्गों का पता लगाना और उन्हें सुदृढ़ करना था।

इस परियोजना की संकल्पना एक कार्य प्रयोगशाला के रूप में की गई थी, जिसमें समुदाय-नेतृत्व वाले साक्ष्य सृजन, उद्यमिता-आधारित आजीविका की प्रायोगिक पहलों और अनुकूलनशील सीख को सम्मिलित किया गया था। कौशल विकास से रोजगार तक के पारंपरिक मॉडलों पर निर्भर रहने के बजाय, कार्य प्रयोगशाला ने

व्यावहारिक, गैर-कक्षागत आजीविका संबंधी हस्तक्षेपों को प्राथमिकता दी, जो प्रतिभागियों की वास्तविक जीवन परिस्थितियों, ग्रामीण परिवेश, शैक्षिक बाधाओं, सुरक्षा संबंधी चिंताओं, संभावित बाजार मांग, उत्पादन लागत, बुनियादी ढाँचे एवं वित्तपोषण संबंधी सीमाओं तथा ग्रामीण लाभार्थियों की सम्मानजनक कार्य की आकांक्षाओं के अनुरूप हों। इसमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किन्नर व्यक्तियों के मुद्दे, अवसरों, बाधाओं और सामाजिक परिवेश की दृष्टि से उनके शहरी समकक्षों से भिन्न हो सकते हैं।



समावेशी आजीविका के अवसरों पर किन्नर प्रतिभागियों के साथ सामुदायिक परामर्श।

कार्यान्वयन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में आजीविका एवं जनसांख्यिकीय मानचित्रण अध्ययन से हुई, जिसे सेवा शिविरों और समुदाय-आधारित डेटा संग्रह के माध्यम से संचालित किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों में शिक्षा से व्यापक स्तर पर वंचित होना, आय में अनिश्चितता, आजीविका संबंधी आकांक्षाएँ तथा व्यावहारिक एवं उद्यम-उन्मुख आजीविका के प्रति प्राथमिकता सामने आईं, जिन्होंने हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करने में सीधे योगदान दिया।

इन साक्ष्यों के आधार पर, उद्यमिता-आधारित आजीविका मॉडलों पर दो कार्य प्रयोगशालाओं के अंतर्गत पाँच अलग-अलग कौशल-आधारित हस्तक्षेपों का प्रायोगिक संचालन किया गया, जिनमें 56 किन्नर सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पहली कार्य प्रयोगशाला का कार्यान्वयन एनआईआरडीपीआर द्वारा सीधे तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र में किया गया। इसमें पोल्लाची में सहोदरी फाउंडेशन के सहयोग से नारियल के खोल पर आधारित उद्यमिता पहल संचालित की गई। इसका मुख्य ध्यान मूल्यवर्धित एवं संसाधन-आधारित उद्यम विकास पर था। इसमें दो स्वयं सहायता समूहों के 11 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें एक सामुदायिक नेता भी शामिल थे।



सतत आजीविका के लिए मसाला प्रसंस्करण एवं उद्यमिता पर व्यावहारिक प्रशिक्षण

दूसरी कार्य प्रयोगशाला का कार्यान्वयन पश्चिम बंगाल में प्लेक्सस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। इसमें आजीविका के चार मॉडल विकसित किए गए, अर्थात् मशरूम की खेती, मसाला प्रसंस्करण, सिलाई एवं परिधान-आधारित उद्यम तथा मुर्गीपालन, जिनमें 45 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। मशरूम, मसाला एवं सिलाई संबंधी मॉडलों के लिए बुनियादी ढाँचे और प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया तथा उद्यम स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं, मुर्गीपालन के क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास का कार्य आगे बढ़ा और इसके लिए प्रशिक्षण बाद में निर्धारित किया गया। उषा इंटरनेशनल के सहयोग से 25 दिवसीय आवासीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में इस परियोजना में तकनीकी कौशल से आगे बढ़कर क्षमता निर्माण, बाजारों एवं संस्थानों से परिचय, सामूहिक एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)-आधारित दृष्टिकोण, मार्गदर्शन तथा संस्थागत समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। निगरानी एवं समीक्षा की प्रक्रियाएँ निरंतर और सीखने पर आधारित थीं, जिससे जलवायु परिस्थितियों, बुनियादी ढाँचे की तैयारी

तथा उद्यमों की परिपक्वता जैसी स्थानीय परिस्थितियों से जुड़ी बाधाओं के अनुसार कार्यों के क्रम में आवश्यक बदलाव करना संभव हुआ।

प्रमुख निष्कर्षों और प्रारंभिक परिणामों से संकेत मिला कि कक्षा-आधारित कौशल प्रशिक्षण या आम लोगों के बीच कार्य करने वाले वेतनभोगी रोजगार की तुलना में व्यावहारिक एवं उद्यमिता-आधारित आजीविका ग्रामीण किन्नर एवं जेंडर-विविधता वाले युवाओं के लिए अधिक सुलभ और स्वीकार्य है। एनआईआरडीपीआर ने आजीविका संबंधी हस्तक्षेपों को शुरू करने, संचालित करने और बनाए रखने में सामुदायिक-आधारित संगठन (सीबीओ) तथा उसके नेता की केंद्रीय भूमिका को पहचाना। प्रारंभिक परिणामों में कौशल के प्रति बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, उद्यम स्थापना की तैयारी, सामूहिक क्षमता तथा बाजारों एवं संस्थानों के साथ जुड़ाव शामिल हैं। इस परियोजना ने कौशल एवं आजीविका, कल्याण, सुरक्षा और गरिमा के बीच परस्पर संबंधों को भी सुदृढ़ किया तथा आजीविका की रूपरेखा में स्वास्थ्य, दस्तावेजीकरण और वित्तीय समावेशन संबंधी सहायता को एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित किया।

यह परियोजना सीआईआरडीएपी के सदस्य देशों में नीति निर्माताओं, ग्रामीण विकास संस्थानों और कार्यकर्ताओं के लिए एक अनुकरणीय रूपरेखा एवं क्रियान्वयन योग्य सुझाव प्रस्तुत करती है, जो समावेशी एवं गरिमापूर्ण ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के व्यापक प्रयासों में योगदान देती है।

परियोजना 2: कनाडा उच्चायोग के सीएफएलआई के सहयोग से परामर्श एवं नीतिगत पैरवी के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किन्नर एवं जेंडर-विविध समुदायों के लिए सतत वेतन-आधारित आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना।

कनाडा फंड फॉर लोकल इनिशिएटिव्स (सीएफएलआई) के सहयोग से संचालित इस दूसरी परियोजना का कार्यान्वयन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय परामर्श, क्षेत्रीय सहभागिता तथा राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत संवाद के माध्यम से किया गया। यह संवाद सामुदायिक-आधारित संगठनों, नागरिक समाज के भागीदारों, सरकारी एजेंसियों, संस्थानों एवं विभागों तथा किन्नर एवं जेंडर-विविध समुदायों के आजीविका समावेशन पर कार्य करने वाले विभिन्न अन्य हितधारकों के सहयोग से आयोजित किया गया। इस परियोजना में आठ गतिविधियाँ शामिल थीं, जिनके विशिष्ट परिणाम निम्नलिखित हैं:

क. समावेशी आजीविका मॉडलों के लिए साक्ष्य आधार को सुदृढ़ करना:

क्षेत्रीय दौरों, परामर्शों तथा सामुदायिक नेताओं, नियोक्ताओं और नागरिक समाज संगठनों के साथ साक्षात्कारों के माध्यम से इस परियोजना ने भारत भर में किन्नर एवं जेंडर-विविध समुदायों के लिए वेतन-आधारित आजीविका के विभिन्न प्रकार के मॉडलों का क्षेत्रीय स्तर पर सत्यापित दस्तावेजीकरण तैयार किया। इससे भविष्य के आजीविका कार्यक्रमों के लिए अनुकरणीय एवं अनुकूलनीय मॉडलों का एक सुव्यवस्थित साक्ष्य आधार उपलब्ध हुआ।

ख. भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने एवं विस्तार के लिए तुलनात्मक विश्लेषणात्मक रूपरेखा:

विभिन्न क्षेत्रों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में प्रलेखित आजीविका मॉडलों और संबंधित नीतिगत साधनों की शक्तियों, सीमाओं, विस्तार की संभावनाओं, स्थिरता तथा अनुकूलनशीलता का आकलन करने के लिए एक तुलनात्मक विश्लेषण उपकरण विकसित किया गया।

ग. **समावेशी रोजगार के लिए बेहतर नीतिगत जानकारी एवं क्रियान्वयन योग्य सुझाव:**

राष्ट्रीय योजनाओं, श्रम कानूनों, क्षेत्रीय कार्यक्रमों, सीएसआर पहलों तथा रोजगार संबंधी रूपरेखाओं के मानचित्रण एवं विश्लेषण के माध्यम से इस परियोजना ने एक समेकित नीतिगत संक्षेप तैयार किया। इसमें मौजूदा विकास एवं कौशल निर्माण रूपरेखाओं के अंतर्गत किन्नर एवं जेंडर-विविध समुदायों के लिए समावेशी वेतन-आधारित रोजगार के मार्गों को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत कमियों, अभिसरण के अवसरों तथा क्रियान्वयन योग्य संभावित उपायों की पहचान की गई।

घ. **आजीविका संबंधी आकांक्षाओं एवं संरचनात्मक बाधाओं पर विस्तारित आँकड़े एवं साक्ष्य:**

अखिल भारतीय जनसांख्यिकीय, आकांक्षाओं, कौशल

एवं आजीविका मानचित्रण अध्ययन के माध्यम से लगभग 450 किन्नर एवं जेंडर-विविध उत्तरदाताओं का एक अनामित आँकड़ा-संग्रह तैयार किया गया, जिसमें उनकी रोजगार स्थिति, कौशल संबंधी विवरण, आजीविका संबंधी आकांक्षाओं तथा सतत रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में आने वाली प्रमुख बाधाओं की जानकारी संकलित की गई। उत्तरदाताओं के एक बड़े हिस्से ने सौंदर्य एवं स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य सत्कार, देखभाल सेवाओं, खुदरा व्यापार, लॉजिस्टिक्स तथा प्रशासनिक कार्यों जैसे क्षेत्रों में वेतन-आधारित रोजगार की ओर बढ़ने में गहरी रुचि व्यक्त की। यह औपचारिक रोजगार के मार्गों की ओर उनकी बढ़ती आकांक्षा के साथ-साथ लक्षित कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुविधा कार्यक्रमों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

ङ **आजीविका कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक साधनों का विकास:**

इस परियोजना के अंतर्गत व्यवहार-उन्मुख ज्ञान के चार उत्पाद तैयार किए गए–एक परिचालन आजीविका मॉडल, परिचालन दिशा-निर्देश, हितधारक सहभागिता रूपरेखा तथा एक ऑनलाइन संसाधन भंडार। इनका उद्देश्य नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं और सामुदायिक संगठनों को किन्नर-समावेशी आजीविका कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने एवं उनका कार्यान्वयन करने में सहायता प्रदान करना है।

च. **ट्रांस आप्ति के माध्यम से प्रौद्योगिकी-सक्षम आजीविका परामर्श की शुरुआत:**

इस परियोजना के अंतर्गत 'ट्रांस आप्ति' नामक वेब-आधारित करियर रुचि मूल्यांकन उपकरण के विकास एवं उपयोग में सहायता प्रदान की गई। यह उपकरण विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जॉन हॉलैंड इंटरेस्ट इन्वेंटरी रूपरेखा पर आधारित है तथा किन्नर व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के लिए एनआईआरडीपीआर द्वारा विकसित 'कौशल आप्ति' अनुप्रयोग के आधार पर तैयार यह उपकरण सामुदायिक-आधारित संगठनों को व्यवस्थित करियर एवं आजीविका परामर्श प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इससे व्यक्तिगत रुचियों एवं कौशलों को उपयुक्त रोजगार क्षेत्रों और प्रशिक्षण के मार्गों के अनुरूप बनाने में सहायता मिलती है।

ग. **सुदृढ़ हितधारक सहभागिता एवं उभरते आजीविका के मार्ग:**

क्षेत्रीय परामर्शों और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नीतिगत संवाद के माध्यम से सरकारी संस्थानों, क्षेत्रीय कौशल परिषदों, नियोक्ताओं, सीएसआर भागीदारों तथा किन्नर समुदाय के संगठनों के बीच सहभागिता बढ़ी। इसके तत्काल परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय परामर्शों के बाद दो किन्नर व्यक्तियों का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) में कौशल प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय हितधारकों ने पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार, देखभाल अर्थव्यवस्था तथा लॉजिस्टिक्स एवं भंडारण जैसे क्षेत्रों में समावेशी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में रुचि व्यक्त की।

छ. **किन्नर-समावेशी कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार में उभरती संस्थागत रुचि:**

परामर्शों से क्षेत्रीय हितधारकों एवं सरकारी संस्थानों के साथ संवाद को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए, गृह प्रबंधन एवं देखभालकर्ता क्षेत्रीय कौशल परिषद ने कौशल विकास कार्यक्रमों, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में किन्नर व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) को विशिष्ट उपायों की सिफारिश की।

इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण प्रदाताओं ने डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत उन क्षेत्रों में किन्नर व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं रोजगार के अवसर तलाशने में रुचि व्यक्त की, जहाँ कार्यबल की मांग बढ़ रही है। यह योजना कौशल प्रशिक्षण एवं नियुक्तियों में संवेदनशील समूहों को शामिल करने को प्रोत्साहित करती है।

ज. **सामुदायिक-आधारित संगठनों (सीबीओ) की क्षमता सुदृढ़ करने की आवश्यकता की पहचान:**

इस परियोजना के अंतर्गत आयोजित क्षेत्रीय परामर्शों, क्षेत्रीय सहभागिता एवं नीतिगत संवाद के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि किन्नर एवं जेंडर-विविध समुदायों के साथ कार्य करने वाले सामुदायिक-आधारित संगठनों को आजीविका कार्यक्रमों एवं रोजगार सुविधा

संबंधी कार्यों में प्रभावी ढंग से सहभागिता करने के लिए व्यवस्थित क्षमता सुदृढ़ीकरण और दीर्घकालिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें अक्सर बड़े स्तर पर आजीविका संबंधी पहलों की रूपरेखा तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक संस्थागत क्षमता, तकनीकी ज्ञान तथा कार्यक्रम प्रबंधन कौशल का अभाव होता है।

इसलिए, केंद्र द्वारा प्रस्तावित अगला महत्वपूर्ण कदम भविष्य की पहलों में प्रमुख प्राथमिकता के रूप में सामुदायिक आधारित संगठनों- का क्षमता विकास एवं संस्थागत (सीबीओ) मार्गदर्शन करना है।

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परामर्श परियोजना का समापन था। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पूर्व सचिव श्रीमती सुमिता दावड़ा ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने सामुदायिक नेताओं, कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विचारकों एवं अन्य प्रतिभागियों से किन्नर समुदाय की आजीविका को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न योजनाओं एवं संसाधनों का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने देश में आजीविका के मॉडलों के आकांक्षा मानचित्रण उपकरण तथा संसाधन भंडार का 'आप्ति-ट्रांस' भी अनावरण किया।



किन्नर आजीविका पहलों की समीक्षा एवं योजना संबंधी परामर्श के दौरान डीडीयू-जीकेवाई आरसी के अधिकारी, एनआईआरडीपीआर के वरिष्ठ संकाय सदस्य, जेंडर कार्यकर्ता, सामुदायिक नेता एवं विशेषज्ञ।

डे-एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यम ऋण आवेदन (आईईएलए) पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



व्यक्तिगत उद्यम ऋण आवेदन (आईईएलए) पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी, डॉ. रवींद्र एस. गावली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीएनआरएम, सीसीडीएम, एनआईआरडीपीआर के साथ।

डे-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यम ऋण आवेदन (आईईएलए) पर 3–5 जून 2026 और 16–19 जून 2026 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में प्रशिक्षकों के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

इन कार्यक्रमों में अधिकारियों, मास्टर प्रशिक्षकों तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनका उद्देश्य उद्यम वित्तपोषण में सहायता प्रदान करने तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच में सुधार करने हेतु उनकी क्षमता को सुदृढ़ करना था।

प्रशिक्षण में आईईएलए रूपरेखा तथा ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की व्यापक समझ विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तकनीकी सत्रों में उद्यम ऋण आवेदन प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रियाओं, दस्तावेजीकरण संबंधी आवश्यकताओं, डिजिटल आवेदन प्रणालियों, ऋण आकलन तथा ऋण आवेदनों की गुणवत्ता और समयबद्ध प्रक्रिया में सुधार की रणनीतियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रमों में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने, सामुदायिक संस्थानों को सुदृढ़ करने, वित्तीय संस्थानों के साथ अभिसरण को सुगम बनाने तथा ऋण संबंधों को बढ़ाने में प्रशिक्षकों की भूमिका पर भी जोर दिया गया।

प्रतिभागियों ने संवादात्मक चर्चाओं, मामला अध्ययनों, व्यावहारिक अभ्यासों तथा अनुभव-साझाकरण सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन सत्रों में क्षेत्रीय स्तर की चुनौतियों पर चर्चा की गई और प्रभावी कार्यान्वयन की कार्यप्रणालियों को प्रस्तुत किया गया। इन कार्यक्रमों ने ज्ञान के आदान-प्रदान एवं क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान किया तथा प्रतिभागियों को व्यक्तिगत उद्यम ऋण आवेदन (आईईएलए) पहल के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करने और डे-एनआरएलएम के अंतर्गत सतत ग्रामीण उद्यमों एवं आजीविका के बेहतर अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशलों से सुसज्जित किया।

लखपति दीदी पहल के अंतर्गत बाजरा एवं सोयाआधारित - उत्पाद बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण



डॉ. सी. कथिरेसन, सह-प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीआईएटी एंड एसजे तथा श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ परामर्शदाता, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी), एनआईआरडीपीआर के साथ प्रतिभागी

कौशल एवं रोजगार के लिए नवाचार एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटी एंड एसजे), एनआईआरडीपीआर ने लखपति दीदी पहल के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के लिए 09–13 जून 2026 तक एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद स्थित ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) में "बाजरा एवं सोया-आधारित उत्पाद बनाने" पर पाँच दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य एसएचजी सदस्यों और सीआरपी के कौशल को पौष्टिक, मूल्यवर्धित बाजरा एवं सोया-आधारित उत्पाद तैयार करने में बढ़ाना था। साथ ही, उद्यमिता एवं सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के बाजरा एवं सोया-आधारित खाद्य उत्पादों की तैयारी, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता मानकों तथा भंडारण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को अपने सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने अथवा उन्हें सुदृढ़ करने में सक्षम बनाने के लिए सत्रों में ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण, विपणन तथा व्यवसाय प्रबंधन के बुनियादी पहलुओं को भी शामिल किया गया।

इस कार्यक्रम में कक्षा सत्रों के साथ व्यापक व्यावहारिक प्रदर्शन भी शामिल थे, जिससे प्रतिभागियों को ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में उपलब्ध उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पाद तैयार करने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण में बाजरा एवं सोया के पोषण संबंधी लाभों, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों की बढ़ती उपभोक्ता मांग तथा अधिक आय अर्जित करने में मूल्य संवर्धन की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला गया।

प्रतिभागियों ने व्यावहारिक अभ्यासों एवं संवादात्मक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने-अपने समुदायों में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा उनका उपयोग करने का आत्मविश्वास प्राप्त किया। इस कार्यक्रम से महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा मिलने, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि उपज का मूल्य संवर्धन प्रोत्साहित होने तथा ग्रामीण परिवारों के लिए सतत आय अर्जित करने के अवसर सृजित करके लखपति दीदी पहल के उद्देश्यों में योगदान मिलने की अपेक्षा है।

पीएसीसीएस के व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



डॉ. आर्यश्री देबप्रिय, सह-प्राध्यापक, सीपीएसडीई, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के साथ व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों एवं पीएसीसीएस की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र (सीपीएसडीई) ने प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसीसीएस) और वृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (एलएएमपीसीएस) के अध्यक्षों/निदेशक मंडल (बीओडी) के सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के लिए 08–12 जून 2026 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में "पीएसीसीएस के व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों" पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम को ओडिशा सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया था।

प्रशिक्षण का उद्देश्य सहकारी समितियों के उभरते व्यवसाय विविधीकरण के अवसरों तथा पीएसीसीएस और एलएएमपीसीएस के सफल परिचालन मॉडलों से परिचित कराकर सहकारी क्षेत्र के नेताओं की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। सत्रों में कृषि निवेश सामग्री के विपणन, कस्टम हायरिंग केंद्रों, भंडारण, मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन तथा अन्य ग्रामीण उद्यमों जैसी गतिविधियों के माध्यम से पारंपरिक ऋण सेवाओं से आगे बढ़कर सहकारी समितियों की भूमिका का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कार्यक्रम में सहकारी शासन, व्यवसाय नियोजन, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटलीकरण तथा सदस्य-केंद्रित सेवा वितरण पर विशेषज्ञ व्याख्यान, संवादात्मक चर्चाएँ, मामला अध्ययन और अनुभव-साझाकरण सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने देश भर की सफल सहकारी समितियों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर भी चर्चा की तथा परिचालन दक्षता, वित्तीय स्थिरता और सदस्यों की सहभागिता में सुधार के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

इस प्रशिक्षण ने सहकारी क्षेत्र के नेताओं को अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा पीएसीसीएस और एलएएमपीसीएस के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने का मंच प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान अर्जित ज्ञान एवं कौशल से प्रतिभागियों को व्यवसाय गतिविधियों में विविधता लाने, सेवा वितरण में सुधार करने तथा ग्रामीण आजीविका एवं स्थानीय आर्थिक विकास में सहकारी संस्थाओं के योगदान को बढ़ाने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।

सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण पद्धति एवं प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



डॉ. रवींद्र एस. गावली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीएनआरएम, सीसीडीएम; डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती, उप निदेशक, डे-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ; तथा श्री आर. रवि नायडू, मिशन कार्यकारी, एनआईआरडीपीआर के साथ प्रतिभागी

डे-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने डे-एनआरएलएम के अंतर्गत स्रोत व्यक्तियों के लिए सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण पद्धति एवं प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करने पर 03–10 जून 2026 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में प्रशिक्षकों का आठ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्रोत व्यक्तियों को सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण विधियों, प्रभावी संचालन कौशल तथा प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करने की तकनीकों से सुसज्जित करके उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना था।

इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के स्रोत व्यक्तियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य शिक्षार्थी-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, योजना बनाने और संचालन करने में उनके ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना था। सत्रों में वयस्क अधिगम के सिद्धांतों, सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण पद्धतियों, संचार एवं संचालन कौशल, प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन, पाठ्यक्रम एवं सत्र नियोजन, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने, सहभागितापूर्ण साधनों के उपयोग तथा अधिगम परिणामों के आकलन की तकनीकों को शामिल किया गया।

प्रतिभागियों ने समूह चर्चाओं, व्यावहारिक अभ्यासों, अनुकरण अभ्यासों, प्रस्तुतियों तथा सहकर्मी-अधिगम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन गतिविधियों से उन्हें वास्तविक प्रशिक्षण परिस्थितियों में सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का अवसर मिला। कार्यक्रम में प्रभावी संचार, अनुभवात्मक अधिगम, प्रतिपुष्टि तंत्र तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए संवादात्मक विधियों के उपयोग पर भी जोर दिया गया।

इस प्रशिक्षण ने प्रतिभागियों को अनुभवों का आदान-प्रदान करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ साझा करने तथा प्रशिक्षकों के रूप में अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान अर्जित ज्ञान एवं कौशल से डे-एनआरएलएम के अंतर्गत क्षमता निर्माण पहलों की गुणवत्ता में सुधार होने तथा देश भर में आजीविका संवर्धन एवं सामुदायिक संस्थानों को सुदृढ़ करने में सहायता करने में सक्षम स्रोत व्यक्तियों का एक सशक्त समूह विकसित होने की अपेक्षा है।

ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु अनुकूल एवं कार्बन तटस्थ योजना पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



डॉ. रवींद्र एस. गावली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीएनआरएम, सीसीडीएम तथा डॉ. अंजन कुमार भांजा, सह-प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर प्रतिभागियों के साथ

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय (एसओईपीआर) ने ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु अनुकूल एवं कार्बन तटस्थ योजना पर 17-19 जून 2026 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में प्रशिक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्रोत व्यक्तियों एवं अधिकारियों की क्षमताओं का निर्माण करना था, ताकि वे स्थानीय विकास योजना में जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन तटस्थता को शामिल करने में ग्राम पंचायतों की सहायता कर सकें।

इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के स्रोत व्यक्तियों, पंचायती राज अधिकारियों तथा विकास कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, शमन तथा सतत ग्रामीण विकास के संबंध में उनकी समझ को सुदृढ़ करना था। सत्रों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की अवधारणा, कार्बन तटस्थ योजना, जलवायु जोखिम आकलन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा सतत भूमि उपयोग पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रतिभागियों को जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ तैयार (जीपीडीपी) करने के लिए योजना संबंधी साधनों एवं सहभागितापूर्ण दृष्टिकोणों से परिचित कराया गया। कार्यक्रम में कार्बन उत्सर्जन कम करने के साथसाथ जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति - अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए सामुदायिक सहभागिता, सरकारी योजनाओं के बीच अभिसरण तथा स्थानीय संसाधनों के उपयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

प्रशिक्षण में विशेषज्ञ व्याख्यान, समूह चर्चाएँ, व्यावहारिक अभ्यास तथा अनुभव-साझाकरण सत्र आयोजित किए गए, जिनसे प्रतिभागियों को विचारों का आदान-प्रदान करने और देश भर की सफल पहलों से सीखने का अवसर मिला। संवादात्मक सत्रों ने प्रतिभागियों को प्रभावी योजना एवं शासन के माध्यम से स्थानीय जलवायु चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचारी उपायों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम ने उन प्रशिक्षकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान किया, जो जलवायु अनुकूल एवं कार्बन तटस्थ विकास रणनीतियों को अपनाने में ग्राम पंचायतों की सहायता करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान एवं कौशल से देश भर में सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन क्षमता में वृद्धि तथा पर्यावरण की दृष्टि से सतत ग्रामीण विकास में योगदान मिलने की अपेक्षा है।

डे-एनआरएलएम के अंतर्गत जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण



डॉ. रवींद्र एस. गावली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीएनआरएम, सीसीडीएम, एनआईआरडीपीआर के साथ डे-एनआरएलएम के अंतर्गत जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

ग्रामीण विकास में आंतरिक लेखा परीक्षा केंद्र (सीआईएआरडी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) के अंतर्गत जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पर 22 से 26 जून 2026 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में प्रशिक्षकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डे-एनआरएलएम के कार्यान्वयन में शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धतियों को अपनाने हेतु अधिकारियों एवं स्रोत व्यक्तियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था।

इस कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) तथा संबंधित संस्थानों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा के सिद्धांतों एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में उनकी समझ को बढ़ाना था। सत्रों में जोखिम आकलन, लेखा परीक्षा नियोजन, परिचालन एवं वित्तीय जोखिमों की पहचान, आंतरिक नियंत्रण तंत्र, लेखा परीक्षा दस्तावेजीकरण, रिपोर्टिंग मानकों तथा अनुवर्ती प्रक्रियाओं को शामिल किया गया। कार्यक्रम के बेहतर निष्पादन तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में जोखिम-आधारित दृष्टिकोणों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया।

प्रतिभागियों ने विशेषज्ञ व्याख्यानों, मामला अध्ययनों, व्यावहारिक अभ्यासों, समूह चर्चाओं तथा अनुभव-साझाकरण सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन सत्रों में आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित क्षेत्रीय स्तर की चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम में लेखा परीक्षा के साधनों एवं पद्धतियों का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया गया, जिससे प्रतिभागियों को व्यवस्थित एवं साक्ष्य-आधारित लेखा परीक्षा संचालित करने के अपने कौशल को सुदृढ़ करने में सहायता मिली।

इस प्रशिक्षण ने आंतरिक लेखा परीक्षा से जुड़े कार्यकर्ताओं एवं प्रशिक्षकों के बीच ज्ञान साझा करने और व्यावसायिक अधिगम के लिए एक मंच प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान अर्जित ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल से डे-एनआरएलएम के अंतर्गत आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने, वित्तीय जवाबदेही बढ़ाने तथा विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान मिलने की अपेक्षा है।

मालदीव गणराज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम






नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लेते हुए मालदीव गणराज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं अधिकारी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद, 21 जून से 6 जुलाई 2026 तक मालदीव गणराज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों की नेतृत्व एवं शासन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा स्थानीय शासन एवं सतत विकास में ज्ञान एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

इस कार्यक्रम में मालदीव गणराज्य की विभिन्न स्थानीय परिषदों एवं सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सहभागितापूर्ण शासन तथा समावेशी विकास के संबंध में उनकी समझ को बढ़ाना है। विशेषज्ञ व्याख्यानों, संवादात्मक चर्चाओं, मामला अध्ययनों, समूह अभ्यासों तथा क्षेत्रीय दौरों के संयोजन के माध्यम से प्रतिभागी भारत के ग्रामीण विकास के अनुभव एवं नवाचारी शासन पद्धतियों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

प्रशिक्षण में नेतृत्व विकास, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), स्थानीय शासन, पंचायती राज, महिला सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तन एवं अनुकूलन क्षमता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सहभागितापूर्ण योजना, सामुदायिक सहभागिता तथा सतत ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। नेतृत्व संबंधी दक्षताओं को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने, नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा स्थानीय विकास योजना में जलवायु अनुकूल दृष्टिकोणों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम से प्रतिभागियों की नेतृत्व एवं प्रबंधकीय क्षमताओं में वृद्धि होने तथा मालदीव गणराज्य में स्थानीय शासन एवं विकास संबंधी पहलों को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होने की अपेक्षा है। यह संस्थागत सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण, विकेंद्रीकृत शासन एवं सतत विकास के क्षेत्रों में भारत और मालदीव के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को भी सुदृढ़ करता है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पूर्ण संतृप्ति लाने एवं समृद्ध ब्लॉक बनाने के लिए बीडीओ नेतृत्व पर बीआईपीएआरडी, गया में ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण



बिहार के गया स्थित बीआईपीएआरडी में आयोजित ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ डॉ. टी. विजय कुमार, सह-प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीईएसडी, एनआईआरडीपीआर

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के समानता एवं सामाजिक विकास केंद्र (सीईएसडी) ने 8–13 जून 2026 तक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बीआईपीएआरडी), गया, बिहार में 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पूर्ण संतृप्ति लाने एवं समृद्ध ब्लॉक बनाने के लिए बीडीओ नेतृत्व' पर छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में बिहार, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के कुल 17 प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) ने भाग लिया। प्रशिक्षण की रूपरेखा बीडीओ की नेतृत्व, प्रबंधन, योजना एवं शासन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई थी, ताकि अभिसरण, कार्यक्रमों की पूर्ण संतृप्ति, साक्ष्य-आधारित योजना, जलवायु अनुकूलन क्षमता, डिजिटल शासन तथा सतत आजीविका संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति प्रदान की जा सके।

उद्घाटन सत्र में डॉ. टी. विजय कुमार, सह-प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीईएसडी, एनआईआरडीपीआर ने बीडीओ को ऐसे विकास नेतृत्वकर्ताओं के रूप में विकसित करने में क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो प्रखंड स्तर पर समावेशी एवं सतत ग्रामीण परिवर्तन को आगे बढ़ाने में सक्षम हों। उन्होंने समृद्ध, अनुकूलनशील एवं समावेशी ग्रामीण समुदायों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूरदर्शी नेतृत्व, प्रभावी अभिसरण तथा परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम में बीडीओ की भूमिका को कार्यक्रम प्रशासक से परिवर्तनकारी विकास नेतृत्वकर्ता के रूप में पुनर्परिभाषित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें एक गाँव के एक दिवसीय क्षेत्रीय भ्रमण सहित कुल 32 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

कार्यक्रम में ग्रामीण शासन एवं विकास के संबंध में प्रतिभागियों के ज्ञान और व्यावहारिक दक्षताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया। प्रमुख सत्रों में परिवर्तनकारी नेतृत्व एवं शासन; अभिसरण पर विशेष जोर देते हुए ग्रामीण विकास योजना; वित्तीय प्रबंधन एवं संसाधन जुटाना; जलवायु अनुकूलन क्षमता एवं सतत विकास; सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से आजीविका संवर्धन; डिजिटल शासन, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार; साक्ष्य-आधारित योजना एवं कार्यक्रमों की पूर्ण संतृप्ति की रणनीतियाँ; तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)-आधारित योजना के लिए युक्तधारा पोर्टल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल थे।

प्रशिक्षण में व्याख्यान, संवादात्मक चर्चाओं, मामला अध्ययनों, भूमिका निर्वहन, समूह अभ्यासों, कार्य योजना, प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों तथा क्षेत्र-आधारित अधिगम सहित सहभागितापूर्ण एवं अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण अपनाए गए। इन पद्धतियों से प्रतिभागियों को क्षेत्रीय चुनौतियों पर गंभीरता से विचार करने तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक समाधान विकसित करने में सहायता मिली।

इस कार्यक्रम का संचालन स्रोत व्यक्तियों की एक प्रतिष्ठित टीम द्वारा किया गया, जिसमें डॉ. ए.ए.ए. फैजी, विशेष सचिव सह निदेशक, अल्पसंख्यक विभाग, बिहार सरकार; डॉ. शशि गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, ग्रामीण अध्ययन विभाग, पटना विश्वविद्यालय, बिहार; श्री पार्थ प्रतिम भट्टाचार्जी, सहायक प्राध्यापक, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी; श्री संजीत कुमार घोष, वरिष्ठ सीपीए, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी; डॉ. सविता कुमारी, आजीविका प्रशिक्षक, बिहार; श्री अब्दुल मोइद, शैक्षणिक परामर्शदाता, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी; तथा श्री तारकेश्वर प्रजापति, युवा पेशेवर सह कनिष्ठ संकाय सदस्य, बीआईपीएआरडी, गया शामिल थे। उन्होंने ग्रामीण विकास प्रशासन एवं नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं पर अपनी विशेषज्ञता साझा की।

इस प्रशिक्षण से समकालीन ग्रामीण विकास परिदृश्य में बीडीओ की बदलती भूमिका के संबंध में समझ बढ़ी, ज्ञान के प्रसार के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का समूह सुदृढ़ हुआ तथा प्रतिभागियों को अपने-अपने प्रखंडों में कार्यान्वयन हेतु स्थानीय संदर्भ के अनुरूप कार्य योजनाएँ तैयार करने में सहायता मिली। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की व्यावहारिक प्रासंगिकता, संवादात्मक रूपरेखा तथा क्षेत्र में उपयोगिता की अत्यधिक सराहना की।

इस पहल से स्थानीय शासन प्रणालियों को सुदृढ़ करने, अभिसरण-आधारित विकास को बढ़ावा देने, सेवा वितरण में सुधार करने तथा समावेशी, सतत एवं अनुकूलनशील ग्रामीण विकास के परिणामों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की अपेक्षा है।

इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. टी. विजय कुमार, प्रमुख, सीईएसडी, एनआईआरडीपीआर ने किया। इसमें डॉ. सत्य रंजन महाकुल, सहायक प्राध्यापक, सीईएसडी तथा श्री तारकेश्वर प्रजापति, युवा फेलो सह कनिष्ठ संकाय सदस्य, बीआईपीएआरडी ने सहयोग दिया। श्री तारसी रेड्डी, प्रशिक्षण प्रबंधक, सीईएसडी ने प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल का संचालन किया।



एसआरएलएम के विकास पेशेवरों के लिए नेतृत्व कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



डॉ. आर. मुरुगेसन, निदेशक, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी तथा डॉ. लखन सिंह, सहायक प्राध्यापक, सीएचआरडी, एनआईआरडीपीआर के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएचआरडी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के विकास पेशेवरों के लिए नेतृत्व कौशल पर 22–25 जून 2026 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संलग्न विकास पेशेवरों की नेतृत्व एवं प्रबंधकीय दक्षताओं को सुदृढ़ करना था।

इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के अधिकारियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के संदर्भ में नेतृत्व के प्रति उनकी समझ को बढ़ाना था। सत्रों में नेतृत्व शैलियों, रणनीतिक सोच, टीम निर्माण, संचार, संघर्ष समाधान, निर्णय लेने, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अभिप्रेरणा तथा परिवर्तन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों ने संस्थानों को सुदृढ़ करने, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करने तथा बेहतर विकास परिणाम प्राप्त करने में प्रभावी नेतृत्व की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया।

प्रशिक्षण में संवादात्मक व्याख्यान, समूह चर्चाएँ, मामला अध्ययन, भूमिका निर्वहन तथा अनुभवात्मक अधिगम गतिविधियाँ शामिल थीं। इन गतिविधियों ने प्रतिभागियों को अपनी नेतृत्व कार्यप्रणालियों पर विचार करने तथा कार्यस्थल की चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों के बीच सहकर्मी अधिगम एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के अवसर भी प्रदान किए गए।

यह कार्यक्रम एसआरएलएम के अधिकारियों की व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक उपयोगी मंच सिद्ध हुआ। प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान एवं कौशल से प्रतिभागियों को टीमों का अधिक प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने, संगठनात्मक कार्यनिष्पादन में सुधार करने तथा डे-एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका पहलों के सफल कार्यान्वयन में योगदान देने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।

आईईएस बैच 2026 के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए ग्रामीण विकास मुद्दे -, चुनौतियाँ, हस्तक्षेप एवं प्रभाव पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



डॉ. एस. ज्योतिष, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीजीएस एंड डीई तथा डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, पाठ्यक्रम निदेशक के साथ प्रतिभागी



डीडीयू-जीकेवाई प्रकोष्ठ की निदेशक श्रीमती संध्या गोपकुमारन तथा कार्यक्रम निदेशक डॉ. पार्थ प्रतिम साहू के साथ प्रतिभागी।

उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडीएफआई), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के 2026 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटी) के लिए 01–05 जून 2026 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में 'ग्रामीण विकास: मुद्दे, चुनौतियाँ, हस्तक्षेप एवं प्रभाव' पर पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थाओं, आजीविका, सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की व्यापक समझ प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी।

कार्यक्रम का शुभारंभ उद्घाटन सत्र से हुआ, जिसका संचालन डॉ. एस. ज्योतिष, प्रोफेसर एवं प्रमुख, स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र (सीपीजीएस एंड डीई) ने किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में ग्रामीण विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम निदेशक डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, सह-प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीईडीएफआई ने कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं रूपरेखा का परिचय दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान चर्चाओं, अनुभवों के आदान-प्रदान तथा प्रमुख विकास संबंधी मुद्दों के आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से संवादात्मक अधिगम पर जोर दिया गया।

प्रशिक्षण में ग्रामीण आजीविका, पंचायती राज, गरीबी एवं असमानता, पोषण, कृषि, श्रम विनियम, कौशल विकास, जलवायु परिवर्तन, जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार (वॉश), ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक जवाबदेही तथा महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। एनआईआरडीपीआर तथा अन्य प्रमुख संस्थानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने उभरती विकास संबंधी चुनौतियों, नीतिगत हस्तक्षेपों तथा ग्रामीण परिवर्तन के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोणों पर सत्र आयोजित किए। प्रतिभागियों ने वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार के लिए सामाजिक अंकेक्षण के महत्व तथा श्रम नीतियों एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण एनआईआरडीपीआर स्थित ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) का भ्रमण था, जहाँ प्रतिभागियों को सतत ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, जैव-स्वच्छता, जल पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों तथा मधुमक्खी पालन, शहद प्रसंस्करण, वर्मी कम्पोस्टिंग एवं मोती प्रसंस्करण जैसे आजीविका-आधारित उद्यमों से परिचित कराया गया। उन्होंने किफायती ग्रामीण आवास प्रौद्योगिकियों तथा ग्रामीण आजीविका एवं स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने वाले नवाचारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।



तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के कंदुकुर मंडल के तिम्मापुर में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के साथ प्रतिभागियों की बातचीत की कुछ झलकियाँ।

जमीनी स्तर पर शासन का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के कंदुकुर मंडल स्थित तिम्मापुर ग्राम पंचायत का क्षेत्रीय भ्रमण आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों तथा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत की और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, स्थानीय शासन प्रणालियों, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, पौधशाला विकास तथा समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। इस भ्रमण में स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में पंचायत के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया तथा यह दर्शाया गया कि योजनाओं के अभिसरण से सेवा वितरण एवं सतत ग्रामीण विकास में किस प्रकार सुधार होता है।

कार्यक्रम में व्याख्यान, मामला अध्ययन, व्यावहारिक चर्चाएँ, क्षेत्रीय अनुभव, प्रशिक्षण-पूर्व एवं प्रशिक्षण-पश्चात आकलन, प्रतिभागियों की प्रस्तुतियाँ तथा प्रतिपुष्टि सत्र शामिल किए गए, ताकि अधिगम का अनुभव रोचक एवं प्रभावी हो। अपने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में बारह आईईएस अधिकारी प्रशिक्षुओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का समापन प्रमाण-पत्र वितरण तथा प्रमुख सीख एवं भावी कार्य योजनाओं पर चर्चा के साथ हुआ।

इस प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास के अवसरों एवं चुनौतियों की गहन समझ प्राप्त हुई तथा विकेंद्रीकृत शासन, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण एवं प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रति उनकी समझ सुदृढ़ हुई। क्षेत्रीय वास्तविकताओं से प्राप्त अनुभव तथा विशेषज्ञों के साथ बातचीत से अधिकारी प्रशिक्षुओं को भारतीय आर्थिक सेवा के सदस्यों के रूप में अपनी भावी भूमिकाओं में नीति निर्माण, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन में सार्थक योगदान देने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।



एनआईआरडीपीआर परिसर स्थित ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) का भ्रमण करते हुए प्रतिभागी

(यह लेख सुश्री ऊर्जा रहेजा, आईईएस अधिकारी प्रशिक्षु द्वारा डॉ(पार्थ प्रतिम साहू के सहयोग से तैयार किया गया है। .

सीएमपीआरपीईडी, एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा द्वारा नगालैंड एसआरएलएम के सीआरपीईपी के लिए विपणन - कौशल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित।



विपणन कौशल पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी एवं स्रोत व्यक्ति सामूहिक छायाचित्र खिंचवाते हुए

ग्रामीण उत्पादों के विपणन एवं संवर्धन तथा उद्यमिता विकास केंद्र (सीएमपीआरपीईडी), एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा ने नगालैंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्यम संवर्धन हेतु सामुदायिक (एनएसआरएलएम) के लिए (ईपी-सीआरपी) संसाधन व्यक्तियों22 से 24 जून 2026 तक एनआईआरडीपीआरएनईआरसी-, गुवाहाटी में विपणन कौशल पर तीन दिवसीय प्रशिक्षकों का (कृषि-गैर) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की ईपी की विपणन क्षमताओं को सुदृढ़ करने -रूपरेखा सीआरपी तथा उन्हें मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ताकि वे आगे नगालैंड की स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों की (एसएचजी) क्षमताओं का निर्माण कर सकें।

कार्यक्रम का उद्घाटन पाठ्यक्रम निदेशक श्री चिरंजी लाल, सहायक निदेशक, सीएमपीआरपीईडी, एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा के स्वागत संबोधन से हुआ। अपने प्रारंभिक संबोधन में उन्होंने ग्रामीण उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं सततता बढ़ाने के लिए एसएचजी को आधुनिक विपणन कौशल से सुसज्जित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस आवासीय कार्यक्रम में कुल 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



संवादात्मक चर्चाओं एवं व्यावहारिक अधिगम गतिविधियों लेते हुए प्रतिभागी

उद्यम विपणन के प्रमुख पहलुओं को प्रशिक्षण में शामिल किया गया, जिनमें ब्रांडिंग, उत्पाद डिजाइन एवं पैकेजिंग, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, बिक्री संचार, खरीदारों का मनोविज्ञान, ईविपणन-, सोशल मीडिया प्रचार, वित्तीय समावेशन तथा कराधानजीएसटी से संबंधित / मुद्दे शामिल थे। कार्यक्रम में व्याख्यान, समूह चर्चा, प्रस्तुतियों एवं व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिससे प्रतिभागियों को विपणन संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण करने तथा एसएचजी उत्पादों के लिए विपणन योजनाएँ तैयार करने में सहायता मिली।

सत्रों का संचालन अनुभवी विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किया गया, जिसमें डॉमुरुगेसन .आर ., निदेशक एवं प्रमुख, एनआईआरडीपीआरएनईआरसी-; डॉ .के .एम .श्रीवास्तव,

सहायक प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी; श्री अश्विनी भट्टाचार्य, राष्ट्रीय स्रोत व्यक्ति; डॉ. रत्ना भुइयां, सहायक प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी; श्री आदर्श अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट; श्री चिरंजी लाल, सहायक निदेशक, सीएमपीआरपीईडी; श्री सुधीर कुमार सिंह, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अधिकारी, एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा; तथा श्री सुरेश प्रसाद, एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा शामिल थे।



प्रतिभागियों का आर्टफेड, गुवाहाटी का भ्रमण

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आकर्षण असम एपेक्स वीवर्स एंड आर्टिजन्स कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (आर्टफेड), गुवाहाटी का अनुभवात्मक भ्रमण था, जहाँ प्रतिभागियों को सहकारी समितियों के नेतृत्व में विपणन, ब्रांडिंग, खुदरा प्रबंधन तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई। इस भ्रमण से प्रतिभागियों को सफल बाजार-संपर्क मॉडलों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ, जिन्हें एसएचजी उद्यमों के लिए अपनाया जा सकता है।

कार्यक्रम का समापन फीडबैक सत्र एवं ई-प्रमाण-पत्रों के वितरण के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के व्यावहारिक स्वरूप तथा ग्रामीण उद्यमों को सुदृढ़ बनाने में इसकी प्रासंगिकता की सराहना की। इस टीओटी से सीआरपी-ईपी की क्षमता में वृद्धि होने की अपेक्षा है, ताकि वे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजिटल विपणन, बिक्री संवर्धन, कराधान तथा बाजार-संपर्क जैसे क्षेत्रों में एसएचजी का मार्गदर्शन कर सकें। इससे नागालैंड में महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों की वृद्धि एवं स्थिरता में योगदान मिलेगा।

संकाय विकास कार्यक्रम -बैच)VI)



संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) के प्रतिभागियों के साथ डॉ. अंजन कुमार भंजा, सहायक प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पंचायती राज (एसओईपीआर), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा 15–19 जून 2026 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) - बैच VI का आयोजन किया गया। पाँच दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य संकाय सदस्यों की शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा उन्हें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में शिक्षण, अधिगम और क्षमता निर्माण के समकालीन दृष्टिकोणों से सुसज्जित करना था।

इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों एवं संगठनों के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। सत्रों में सहभागितापूर्ण शिक्षण पद्धतियों, पाठ्यक्रम अभिकल्पना, मामला-आधारित अधिगम, शिक्षा के लिए डिजिटल उपकरणों, अनुसंधान पद्धतियों, शैक्षणिक लेखन तथा प्रभावी प्रशिक्षण तकनीकों सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण, परिणाम-आधारित शिक्षा तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया।

प्रतिभागियों ने संवादात्मक व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, व्यावहारिक अभ्यासों, प्रस्तुतियों एवं सहकर्मी-अधिगम सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन गतिविधियों से विचारों के आदान-प्रदान, संस्थागत अनुभवों को साझा करने तथा शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नवाचारी कार्यप्रणालियों का पता लगाने के अवसर प्राप्त हुए।

इस कार्यक्रम ने विभिन्न संस्थानों के संकाय सदस्यों के बीच व्यावसायिक अधिगम एवं सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान अर्जित ज्ञान एवं कौशल से शिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों की गुणवत्ता में वृद्धि होने की अपेक्षा है, जिससे शैक्षणिक संस्थान सुदृढ़ होंगे तथा ग्रामीण विकास क्षेत्र में मानव संसाधन विकास अधिक प्रभावी होगा।

एमजेसीईटी ने यूबीए आउटरीच पहल के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा को सुदृढ़ किया

डॉ. मोहम्मद सदाक अली खान
कार्यक्रम समन्वयक, यूबीए प्रकोष्ठ,
मुफ़्फ़ख़म जाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एमजेसीईटी), हैदराबाद
डॉ. वी. धर्म सिंह
सह-समन्वयक, यूबीए प्रकोष्ठ,
मुफ़्फ़ख़म जाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एमजेसीईटी), हैदराबाद





उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत यूबीए द्वारा गोद लिए गए गाँवों में अध्ययन सामग्री वितरण के दौरान बच्चों एवं समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए डॉ. लखन सिंह, यूबीए सह-समन्वयक, एनआईआरडीपीआर तथा एमजेसीईटी के संकाय सदस्य

मुफ़्फ़ख़म जाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एमजेसीईटी), हैदराबाद, उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के अंतर्गत एक सहभागी संस्थान है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के मार्गदर्शन में सामुदायिक संपर्क गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निरंतर प्रदर्शित कर रहा है। ऐसी ही एक पहल के अंतर्गत 20 जून 2026 को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के यूबीए द्वारा गोद लिए गए गाँवों के बच्चों को आवश्यक अध्ययन सामग्री दान एवं वितरित की गई।

इस आउटरीच कार्यक्रम का नेतृत्व एमजेसीईटी के यूबीए समन्वयकों, डॉ. मोहम्मद सदाक अली खान, कार्यक्रम समन्वयक, यूबीए प्रकोष्ठ तथा डॉ. वी. धर्म सिंह, सह-समन्वयक, यूबीए प्रकोष्ठ ने किया। इस पहल की सक्रिय रूप से योजना बनाने एवं कार्यान्वयन में सहयोग देने वाले संकाय सदस्यों की समर्पित टीम में डॉ. मोहम्मद विकार मोहिउद्दीन, डॉ. मोहम्मद हाशम अली, डॉ. शेख इरफान सदाक, डॉ. मोहम्मद रफी तथा श्री सी. रविंदर शामिल थे। एनआईआरडीपीआर के यूबीए सह-समन्वयक डॉ. लखन सिंह ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने गाँव के प्रतिनिधियों, विद्यालय प्राधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के साथ बातचीत की तथा संस्थान और ग्रामीण गोद लिए गए गाँवों के बीच अधिक सुदृढ़ सहभागिता को प्रोत्साहित किया।

इन गाँवों में गुड़ी थांडा, टुनीकिला थांडा, हनुमान नगर, दासुगड्डा थांडा तथा कोयगुंडा थांडा शामिल हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को नोटबुक, स्कूल बैग, पेन, पेंसिल, ड्राइंग बुक, क्रेयॉन तथा अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्री वितरित की गई। शैक्षणिक सामग्री वितरित करने के अतिरिक्त, संकाय सदस्यों ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से बातचीत की तथा शिक्षा, विद्यालय में नियमित उपस्थिति, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए आवश्यक शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच में सुधार हुआ, सामुदायिक सहभागिता सुदृढ़ हुई तथा उच्च शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण समुदायों के बीच सार्थक साझेदारी को बढ़ावा देकर उन्नत भारत अभियान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया गया।

एनआईआरडीपीआर यूबीए के सहभागी संस्थानों को ऐसी सामुदायिक उन्मुख पहल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ संस्थान और गाँव के बीच साझेदारी को सुदृढ़ करती हैं। इस प्रकार की आउटरीच गतिविधियाँ शैक्षणिक सहभागिता को ग्रामीण समुदायों के लिए ठोस विकासात्मक परिणामों में परिवर्तित करके उन्नत भारत अभियान के मूल दर्शन को प्रतिबिंबित करती हैं।

एनआईआरडीपीआर द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस **2026** मनाया गया









एनआईआरडीपीआर परिसर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेते हुए संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, प्रशिक्षु एवं विद्यार्थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा 21 जून 2026 को हैदराबाद स्थित इसके राजेंद्रनगर परिसर में उत्साहपूर्वक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में संकाय सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया, जो स्वास्थ्य, कल्याण एवं संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देने के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करता है।

योग सत्र का संचालन अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों को आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित सामान्य योग प्रोटोकॉल के आधार पर विभिन्न योगासनों, श्वास संबंधी अभ्यासों (प्राणायाम) एवं ध्यान तकनीकों का अभ्यास कराया। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ इन अभ्यासों में भाग लिया तथा बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण एवं तनाव प्रबंधन के लिए दैनिक जीवन में योग को शामिल करने के महत्व को रेखांकित किया।

सभा को संबोधित करते हुए संस्थान के अधिकारियों ने विश्व को भारत के अमूल्य योगदान के रूप में योग के महत्व पर प्रकाश डाला तथा प्रतिभागियों को समग्र स्वास्थ्य के लिए इसे नियमित अभ्यास के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उत्पादकता, भावनात्मक कल्याण एवं जीवन की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने में योग की भूमिका को भी रेखांकित किया।

कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों द्वारा योग को जीवनशैली के रूप में अपनाने तथा अपने परिवारों एवं समुदायों में इसके अभ्यास को बढ़ावा देने की शपथ के साथ हुआ, जो इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह की भावना को प्रतिबिंबित करता है।

30-दिवसीय सामुदायिक लेखा परीक्षक प्रमाणन कार्यक्रम



श्री चरणजीत सिंह, पूर्व अपर सचिव, एमओआरडी; डॉ. रवींद्र एस. गावली, प्रोफेसर; डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती, उप निदेशक; तथा श्री आर. रवि नायडू, मिशन कार्यकारी, डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर के साथ प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ द्वारा 20 मई से 24 जून 2026 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में 30-दिवसीय सामुदायिक लेखा परीक्षक प्रमाणन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमाणित सामुदायिक लेखा परीक्षकों का एक संवर्ग विकसित करना था, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समुदाय-आधारित निगरानी को सुदृढ़ करने में सक्षम हों।

एक माह तक चले इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं उनके परिसंघों का सामुदायिक अंकेक्षण करने के लिए प्रतिभागियों के ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल का विकास करना था। प्रशिक्षण में सामुदायिक अंकेक्षण के सिद्धांत, वित्तीय प्रबंधन, लेखा-जोखा रखना, अभिलेखों का सत्यापन, अंकेक्षण प्रक्रियाएँ, रिपोर्टिंग प्रारूप, अनुपालन संबंधी आवश्यकताएँ तथा सामुदायिक संस्थानों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सहभागितापूर्ण दृष्टिकोणों का उपयोग शामिल था।

कार्यक्रम में कक्षा सत्रों के साथ व्यावहारिक अभ्यास, मामला अध्ययन, क्षेत्र-आधारित अधिगम तथा अंकेक्षण का व्यावहारिक अभ्यास शामिल किया गया। प्रतिभागियों को संचार कौशल, अंकेक्षण में नैतिकता, रिपोर्ट तैयार करने तथा वित्तीय एवं परिचालन संबंधी कमियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया गया। संवादात्मक चर्चाओं एवं अनुभव-साझाकरण सत्रों से प्रतिभागियों को क्षेत्रीय अनुभवों से सीखने तथा समुदाय-आधारित निगरानी प्रणालियों की अपनी समझ को सुदृढ़ करने का अवसर मिला।

इस प्रमाणन कार्यक्रम से प्रतिभागियों को अपने-अपने राज्यों में सामुदायिक अंकेक्षण करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। प्रशिक्षित सामुदायिक लेखा परीक्षकों से वित्तीय अनुशासन में सुधार लाने, सामुदायिक संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा है।

आजीविका, स्वयं के राजस्व स्रोत एवं (ओएसआर) नेतृत्व वाले -समावेशी विकास के लिए पंचायत ग्रामीण हाट प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला



श्री चरणजीत सिंह, पूर्व अपर सचिव, एमओआरडी; डॉ. रवींद्र एस. गावली; डॉ. एस. ज्योतिस; तथा डॉ. अंजन कुमार भंजा, एनआईआरडीपीआर के साथ कार्यशाला के प्रतिभागी

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पंचायती राज (एसओईपीआर), एनआईआरडीपीआर द्वारा 11–12 जून 2026 को संस्थान के हैदराबाद परिसर में आजीविका, स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) एवं समावेशी विकास के लिए पंचायत-नेतृत्व वाले ग्रामीण हाट प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य पंचायती राज विभागों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), विषय विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं एवं विकास कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें आर्थिक विकास एवं स्थानीय शासन के केंद्रों के रूप में ग्रामीण हाटों के पंचायत-नेतृत्व वाले प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श किया गया।

दो दिवसीय कार्यशाला में आजीविका को बढ़ावा देने, स्थानीय उत्पादकों की बाजार तक पहुँच बढ़ाने तथा ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) उत्पन्न करने में ग्रामीण हाटों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। तकनीकी सत्रों में ग्रामीण हाटों की योजना एवं प्रबंधन की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, शासन संबंधी रूपरेखाओं, अवसंरचना विकास, डिजिटल नवाचारों, मूल्य श्रृंखला संपर्कों तथा किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), कारीगरों एवं अन्य ग्रामीण उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया।

प्रतिभागियों ने विभिन्न राज्यों में पंचायतों द्वारा प्रबंधित ग्रामीण हाटों के सफल मॉडलों पर संवादात्मक चर्चाओं एवं अनुभव-साझाकरण सत्रों में भाग लिया। विचार-विमर्श के दौरान ग्रामीण बाजारों को समावेशी एवं सतत आर्थिक केंद्रों के रूप में सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों, संस्थागत तंत्रों तथा अभिसरण के अवसरों पर भी चर्चा की गई। पारदर्शिता बढ़ाने, सेवा वितरण में सुधार करने तथा स्थानीय आर्थिक विकास के जीवंत केंद्रों के रूप में ग्रामीण हाटों का उपयोग करने हेतु पंचायतों को सक्षम बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

इस कार्यशाला ने देशभर में पंचायत-नेतृत्व वाले ग्रामीण हाट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए विचारों के आदान-प्रदान एवं व्यावहारिक रणनीतियों की पहचान करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। चर्चाओं से प्राप्त सिफारिशों से सतत ग्रामीण बाजारों के विकास, आजीविका के अवसरों में सुधार, पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों (ओएसआर) में वृद्धि तथा समावेशी ग्रामीण विकास में योगदान मिलने की अपेक्षा है।

राष्ट्रीय स्रोत व्यक्तियों के लिए वन स्टॉप फैसिलिटी (ओएसएफ) कार्यान्वयन रणनीति पर कार्यशाला



डॉ. रवींद्र एस. गावली, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीएनआरएम, सीसीडीएम तथा डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती, उप निदेशक, डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर के साथ वन स्टॉप फैसिलिटी (ओएसएफ) कार्यान्वयन रणनीति पर दो दिवसीय कार्यशाला के प्रतिभागी

डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर द्वारा 01–02 जून 2026 को संस्थान के हैदराबाद परिसर में राष्ट्रीय स्रोत व्यक्तियों (एनआरपी) के लिए वन स्टॉप फैसिलिटी (ओएसएफ) कार्यान्वयन रणनीति पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय स्रोत व्यक्तियों की क्षमता का विकास करना तथा उन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत वन स्टॉप फैसिलिटी (ओएसएफ) के प्रभावी कार्यान्वयन एवं विस्तार के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से सुसज्जित करना था।

इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय स्रोत व्यक्तियों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के अधिकारियों तथा कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें ओएसएफ पहल के कार्यान्वयन ढाँचे एवं परिचालन रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। सत्रों में वन स्टॉप फैसिलिटी के दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों तथा उद्यम विकास को सुगम बनाने, वित्तीय एवं व्यवसाय विकास सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों एवं ग्रामीण उद्यमियों के लिए सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका का अवलोकन प्रस्तुत किया गया।

तकनीकी सत्रों में ओएसएफ मॉडल के प्रमुख घटकों, संस्थागत व्यवस्थाओं, परिचालन दिशानिर्देशों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, निगरानी तंत्र तथा जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में सहयोग

देने के लिए राष्ट्रीय स्रोत व्यक्तियों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को वित्तीय संस्थानों, सरकारी विभागों एवं अन्य हितधारकों के साथ अभिसरण को सुदृढ़ करने की रणनीतियों से भी परिचित कराया गया, ताकि निर्बाध सेवा वितरण एवं ग्रामीण उद्यमों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

कार्यशाला में संवादात्मक प्रस्तुतियाँ, समूह चर्चाएँ, व्यावहारिक अभ्यास एवं अनुभव-साझाकरण सत्र आयोजित किए गए, जिनसे प्रतिभागियों को क्षेत्रीय अनुभवों का आदान-प्रदान करने, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करने तथा व्यावहारिक समाधान तलाशने का अवसर मिला। ओएसएफ कार्यान्वयन रणनीति की साझा समझ विकसित करने, हितधारकों के बीच समन्वय सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली सहायता की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

एनआईआरडीपीआर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 मनाया गया





विश्व पर्यावरण दिवस 2026 समारोह के दौरान एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ केरल के प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा 5 जून 2026 को हैदराबाद स्थित अपने राजेंद्रनगर परिसर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की इस वर्ष की आधिकारिक थीम, "प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए।" के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस 2026 मनाया गया। अज़रबैजान गणराज्य द्वारा वैश्विक स्तर पर आयोजित इस दिवस के समारोह में सामूहिक जलवायु कार्रवाई एवं पर्यावरण संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। एनआईआरडीपीआर में चल रहे एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग ले रहे केरल के प्रतिभागियों ने समारोह में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे समुदायों के अपने बहुमूल्य क्षेत्रीय अनुभव साझा किए।

कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से निपटने एवं सुदृढ़ समुदायों के निर्माण में प्रकृति-आधारित समाधानों के महत्व पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने बढ़ते तापमान, पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण एवं चरम मौसमी घटनाओं से उत्पन्न हो रही चुनौतियों पर चर्चा की तथा सतत जीवनशैली एवं समुदाय-नेतृत्व वाली पर्यावरणीय कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया। वैश्विक अभियान संदेश #NowForClimate के माध्यम से व्यक्तियों एवं संस्थानों को पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सार्थक उपाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

समारोह का एक प्रमुख आकर्षण एनआईआरडीपीआर में शुरू की गई नई पहल "गिफ्ट ए प्लांट" का शुभारंभ था, जिसका उद्देश्य सरल लेकिन प्रभावशाली कार्यों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना है। इस पहल के अंतर्गत प्रतिभागियों ने पौधे भेंट किए, जो कार्यक्रम के बाद भी पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक थे। इस पहल के संस्थान में वार्षिक परंपरा बनने की अपेक्षा है, जिससे यह संदेश सुदृढ़ होगा कि पर्यावरण में स्थायी बदलाव की शुरुआत व्यक्तिगत जिम्मेदारी से होती है।

कार्यक्रम में एनआईआरडीपीआर की मिशन लाइफ पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें भारत सरकार के पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ) आंदोलन को दर्शाया गया। डॉक्यूमेंट्री में मिशन लाइफ के तीन प्रमुख चरणों–मांग में बदलाव, आपूर्ति में बदलाव तथा नीति में बदलाव–पर प्रकाश डाला गया और प्रतिभागियों को अपने दैनिक जीवन में सतत कार्यप्रणालियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के बाद प्रतिभागियों के बीच अपने-अपने राज्यों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं क्लस्टर स्तरीय परिसंघों (सीएलएफ) की गतिविधियों में लाइफ के सिद्धांतों को शामिल करने पर सार्थक चर्चा हुई।

समारोह का समापन पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक स्तर पर जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ करने की नई प्रतिबद्धता के साथ हुआ। "गिफ्ट ए प्लांट" जैसी पहलों एवं मिशन लाइफ के प्रचार-प्रसार के माध्यम से एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण विकास के अभिन्न अंग के रूप में पर्यावरण जागरूकता, सतत जीवनशैली एवं जलवायु अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

.

ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए मानक (जीपीडीपी) तैयार करने पर कार्यशाला (एसओपी) संचालन प्रक्रिया



डॉअंजन कुमार भंजा ., सहायक प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी तथा तंद्रा मंडल, सहायक प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के प्रतिभागी (एसओपी) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (जीपीडीपी)

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पंचायती राज (एसओईपीआर), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा 24–25 जून 2026 को संस्थान के हैदराबाद परिसर में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी एवं कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने हेतु विशेषज्ञों, संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में जीपीडीपी की योजना प्रक्रिया को मानकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि अधिक प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। विचार-विमर्श में जीपीडीपी तैयार करने के विभिन्न चरणों को शामिल किया गया, जिनमें सहभागितापूर्ण योजना, आवश्यकता आकलन, संसाधन मानचित्रण, योजनाओं का अभिसरण, स्थानीय विकास आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करना तथा निगरानी एवं मूल्यांकन शामिल थे। प्रतिभागियों ने ग्राम पंचायतों में योजना की गुणवत्ता एवं एकरूपता में सुधार के लिए संस्थागत भूमिकाओं, समय-सीमाओं एवं परिचालन दिशानिर्देशों पर भी चर्चा की।

तकनीकी सत्रों में प्रस्तुतियाँ, समूह चर्चाएँ एवं सामूहिक प्रारूपण अभ्यास आयोजित किए गए, जिनसे प्रतिभागियों को मौजूदा योजना प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों की पहचान करने तथा एक सुदृढ़ एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल एसओपी विकसित करने के लिए व्यावहारिक उपाय सुझाने का अवसर मिला। कार्यशाला में जीपीडीपी प्रक्रिया में सतत विकास, समावेशी योजना एवं साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने को शामिल करने पर भी जोर दिया गया।

इस कार्यशाला ने जीपीडीपी तैयार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के प्रमुख घटकों को अंतिम रूप देने हेतु एक सहयोगात्मक मंच प्रदान किया।

स्वयं के राजस्व स्रोत में वृद्धि एवं नवाचार रणनीतियों पर (ओएसआर) राष्ट्रीय कार्यशाला



डॉअंजन कुमार भंजा ., सहायक प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर के साथ स्वयं के राजस्व स्रोत में वृद्धि एवं नवाचार रणनीतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागी (ओएसआर)

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पंचायती राज (एसओईपीआर), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा 22–23 जून 2026 को संस्थान के हैदराबाद परिसर में स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) में वृद्धि एवं नवाचार रणनीतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस कार्यशाला में ग्राम पंचायतों की राजस्व सृजन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए नवाचारी दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श करने हेतु पंचायती राज विभागों के अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं एवं विकास कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

कार्यशाला में कर एवं गैर-कर राजस्व संग्रहण में सुधार, पंचायत की परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन, उपयोगकर्ता शुल्क तथा स्थानीय संसाधन जुटाने की नवाचारी कार्यप्रणालियों के माध्यम से स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तकनीकी सत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए नीतिगत सुधारों, संस्थागत तंत्रों, डिजिटल समाधानों तथा विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए सफल मॉडलों पर चर्चा की गई।

प्रतिभागियों ने वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार करने तथा स्थानीय राजस्व जुटाने में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने से संबंधित संवादात्मक चर्चाओं, मामला अध्ययन प्रस्तुतियों एवं अनुभव-साझाकरण सत्रों में भाग लिया। विचार-विमर्श में ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने हेतु अभिसरण, साक्ष्य-आधारित योजना एवं क्षमता निर्माण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

इस कार्यशाला ने विचारों के आदान-प्रदान एवं विभिन्न राज्यों में अपनाई जा सकने वाली नवाचारी कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। चर्चाओं से प्राप्त सिफारिशों से पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने, सेवा वितरण में सुधार करने तथा स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि के माध्यम से सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।

पलायन पर कौशल की जीतएक व्यक्ति जिसने : गाँव की सोच बदल दी

श्री श्यामला सतीश कुमार
पीजीडीएम-आरएम, एनआईआरडीपीआर
syamalasatishkumar@nirdpr.org.in





लेखक श्री श्यामला सतीश कुमार, पीजीडीएमआरएम के विद्यार्थी-, एनआईआरडीपीआर, कप्पात्रल्ला की अपनी यात्रा के दौरान ग्रामीणों से बातचीत करते हुए

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के एक छोटे से गाँव कप्पात्रल्ला के शुष्क क्षेत्र में जीवन कभी आसान नहीं रहा है। कई परिवारों के लिए जीवन-यापन एक कठिन विकल्प पर निर्भर था, जो वर्षों से एक परंपरा बन गया था–पलायन। हर मौसम में पुरुष और महिलाएँ अपने घरों को छोड़कर आसपास के कस्बों और शहरों में जाते थे और अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त धन कमाने हेतु मजदूरी करते थे। अधिकांश ग्रामीणों का मानना था कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनके विचार से, गाँव में स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन या अवसर उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, लगभग हर परिवार का कम-से-कम एक सदस्य हर वर्ष काम की तलाश में पलायन करता था।

जब मैंने आजीविका अध्ययन के एक भाग के रूप में कप्पात्रल्ला का दौरा किया, तो मैंने बार-बार यही कहानी सुनी। लोग अनिश्चितता, स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी और आजीविका कमाने के लिए अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता के बारे में बात करते थे। पलायन जीवन का इतना सामान्य हिस्सा बन गया था कि कई ग्रामीण आगे बढ़ने का कोई दूसरा रास्ता सोच भी नहीं सकते थे। फिर भी, संघर्ष और पलायन की इन कहानियों के बीच एक व्यक्ति ऐसा था, जिसकी यात्रा सबसे अलग थी। उसकी कहानी ने चुपचाप इस धारणा को चुनौती दी कि पलायन ही जीवन-यापन का एकमात्र रास्ता है। उसका नाम रामय्या था।

रामय्या मूल रूप से कप्पात्रल्ला का निवासी नहीं था। वह गुंटूर जिले से आया था और अन्य लोगों की तरह काम की तलाश में मौसमी रूप से पलायन करता था। हालाँकि, उसमें कुछ अलग बात थी। अधिकांश प्रवासी मजदूरों के विपरीत, जो निर्माण स्थलों या खेतों में काम करते थे, रामय्या अपने साथ एक कौशल लेकर चलता था–वह तिरपाल की सिलाई और मरम्मत का काम जानता था। यह काम सीखने से पहले वह एक किसान था। लेकिन खेती में बार-बार हुए नुकसान के कारण उसके लिए अपने परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया था। हार मानने के बजाय, उसने एक विशेष कौशल सीखा, जिसने अंततः उसका जीवन बदल दिया।

जब रामय्या कप्पात्रल्ला पहुँचा, तो उसने एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। गाँव के कई घरों की छतें अस्थायी या अर्ध-स्थायी थीं। खराब मौसम से घरों, फसलों और सामानों की सुरक्षा के लिए आमतौर पर तिरपाल की चादरों का उपयोग किया जाता था। ये चादरें अक्सर फट जाती थीं या क्षतिग्रस्त हो जाती थीं, विशेषकर बरसात के मौसम में। मरम्मत की आवश्यकता तो सभी को थी, लेकिन बहुत कम लोगों के पास यह काम करने का कौशल था। रामय्या ने इसे समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा।

धीरे-धीरे, ग्रामीण मदद के लिए उसके पास आने लगे। वह फटी हुई चादरों की सिलाई करता, क्षतिग्रस्त आवरणों की मरम्मत करता और यह सुनिश्चित करता कि परिवार अपने घरों और फसलों की सुरक्षा कर सकें। उसका काम भरोसेमंद था और उसकी चर्चा तेजी से फैलने लगी। एक छोटी-सी सेवा के रूप में शुरू हुआ यह काम जल्द ही आय का एक नियमित स्रोत बन गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह समुदाय की एक वास्तविक आवश्यकता पूरी कर रहा था। वह केवल पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि ऐसी उपयोगी सेवा प्रदान कर रहा था, जिस पर लोग निर्भर थे। इसके परिणाम उल्लेखनीय थे।

जहाँ कई मौसमी प्रवासी मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करके लगभग ₹10,000 से ₹15,000 प्रति माह कमाते थे, वहीं रामय्या अपने कुशल कार्य के माध्यम से लगभग ₹30,000 प्रति माह कमा रहा था। इस आय से वह अपने खर्चों को आसानी से पूरा कर पा रहा था, अपने परिवार को घर पैसे भेज पा रहा था और भविष्य के लिए बचत भी कर पा रहा था। कई ग्रामीणों के लिए यह आश्चर्यजनक था। वे हमेशा यही मानते आए थे कि पलायन का अर्थ कम मजदूरी के लिए संघर्ष करना है, लेकिन रामय्या ने दिखाया कि सही कौशल पूरी तरह से अलग परिणाम दे सकता है।

उसकी सफलता का कारण भाग्य नहीं था। इसके पीछे तीन प्रमुख कारक थे: उसके पास एक विशेष कौशल था, उसे बहुत कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था और पूरे वर्ष उसकी सेवाओं की निरंतर माँग बनी रहती थी। इन कारकों ने मिलकर उसे एक स्थिर और सम्मानजनक आजीविका स्थापित करने में सहायता की। उसकी कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण बन गई कि कौशल-आधारित कार्य अक्सर अकुशल श्रम की तुलना में अधिक लाभदायक हो सकता है।

समय के साथ, ग्रामीणों ने पलायन को अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उनमें से कई ने स्वीकार किया कि वे हमेशा यही मानते थे कि गाँव छोड़ना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। हालाँकि, रामय्या को सफल होते देखकर उन्होंने इस धारणा पर सवाल उठाना शुरू किया। वे यह समझने लगे कि यदि लोगों के पास सही कौशल और सहयोग हो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। उसके काम ने व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान खोजने के विषयों पर चर्चा को प्रोत्साहित किया।

रामय्या की यात्रा में एक गहरा संदेश भी निहित था। पलायन अपने आप में आवश्यक रूप से कोई समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पलायन मजबूरी में हो रहा है या अवसर के कारण। कई परिवारों के लिए पलायन कठिनाइयों का सामना करने का एक उपाय है। लेकिन जब लोगों के पास उपयोगी कौशल होते हैं, तो पलायन आवश्यकता के बजाय एक विकल्प बन सकता है। यह उन्हें सम्मान, वित्तीय सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर प्रदान कर सकता है।

आज रामय्या को दूसरों से अधिक कमाई करने के लिए नहीं, बल्कि अपने गाँव की सोच बदलने के लिए याद किया जाता है। उसने साबित किया कि सतत आजीविका केवल प्राकृतिक संसाधनों या सरकारी सहायता के आधार पर ही स्थापित नहीं होती। यह कौशल, रचनात्मकता और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर भी आधारित होती है। दृढ़ संकल्प और विशेषज्ञता रखने वाला एक व्यक्ति लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देने और पूरे समुदाय को अपने भविष्य के बारे में अलग ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करने में सक्षम हुआ।

कप्पात्रल्ला की कहानी केवल पलायन के बारे में नहीं है, बल्कि छिपी हुई संभावनाओं को सामने लाने के बारे में है। यह हमें याद दिलाती है कि ग्रामीण समुदायों में अक्सर ऐसे अवसर मौजूद होते हैं, जो तब तक दिखाई नहीं देते, जब तक कोई उन्हें खोजने के लिए पहला कदम नहीं उठाता। अपनी मेहनत और कौशल के माध्यम से रामय्या ने दिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ा बदलाव एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होता है, जो आगे बढ़ने के किसी दूसरे रास्ते पर विश्वास करने का साहस रखता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनईएससीएपी के उत्कृष्टता केंद्रों में से एक के रूप में मान्यता - प्राप्त यह संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श की परस्पर संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों (पीआरआई), बैंकरों, गैरसरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों की क्षमता का विकास करता है। यह संस्थान तेलंगाना राज्य के - ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में स्थित है। एनआईआरडीपीआर ने वर्ष2008 में अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। हैदराबाद स्थित मुख्य परिसर के अतिरिक्त, इस संस्थान का गुवाहाटी, असम में उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय केंद्र-, नई दिल्ली में एक शाखा तथा वैशाली, बिहार में एक कैरियर मार्गदर्शन केंद्र है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेंद्रनगर, हैदराबाद

NATIONAL INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
RAJENDRANAGAR, HYDERABAD - 500 030
PHONE: (040) 24008473, FAX: (040) 24008473
E-MAIL: CDC.NIRD@GOV.IN, WEBSITE: WWW.NIRDPR.ORG.IN

श्री टी. के. अनिल कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर
सहायक संपादक: कृष्णा राज के. एस.
अपर्णा वी. आर.
मुखपृष्ठ अभिकल्पना: वी. जी. भट
प्रकाशक:
ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीपीजीएस एवं डीई, एनआईआरडीपीआर की ओर से, राजेंद्रनगर, हैदराबाद – 500 030